www.tamsasanket.com
वर्ष: 05 | अंक 224 | लखनऊ
शुक्रवार
27 फ़रवरी 2026 | पृष्ठ: 04 | मूल्य: ₹ 2
आज़ादी का अमृत महोत्सव
समूह संपादक- डॉ. ओ.पी. मिश्रा
https://epaper.tamsasanket.com

दैनिक तमसा संकेत

लखनऊ व अम्बेडकर नगर से एक साथ प्रकाशित
डॉ. लोहिया की जन्म भूमि से सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र

मौसम
सूर्योदय: 06:32
सूर्यास्त: 06:06
अधिकतम: 31°00
न्यूनतम: 16°00

पेज 03 >>

विशेष समाचार: देश की राजधानी दिल्ली बनी... >> पेज 02 | केजीएमयू में मजारें तोड़ने की कार्रवाई ... >> पेज 04 | 'फैमिली में कोई नेगेटिविटी नहीं है' ...

"मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो में कई जी2जी (गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट) और जी2बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) स्तर की बैठकों में भाग लिया, जहां भारतीय दूतावास के सहयोग से जापानी उद्योग समूहों से व्यापक संवाद हुआ। उन्होंने यामानाशी प्रशासन को सक्रिय पहल कर निवेश संवाद को आगे बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद दिया।

योगी ने 500 की स्पीड वाली ट्रेन में सफर किया, जापान में बच्चे ने पैर छुए

यूपी और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन पर एमओयू साइन

दौरा

तमसा संकेत, एजेंसी

यामानाशी (जापान)/लखनऊः सिंगापुर दौरे के बाद जापान दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी सरकार ने जापान के यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में प्रदेश की नई विकास नीति और निवेश संभावनाओं को वैश्विक उद्योग जगत के सामने प्रमुखता से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने संबोधन में

योगी ने जापान के यामानाशी में मैग्लेव ट्रेन से यात्रा की।

स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है और यही परिवर्तन आज प्रदेश की तेज आर्थिक प्रगति का आधार बना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

"रिएक्टिव से प्रोएक्टिव" मॉडल बना विकास का आधार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन व्यवस्था में आए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले समस्याओं पर प्रतिक्रिया देने वाली व्यवस्था थी, जबकि अब उत्तर प्रदेश ने प्रोएक्टिव गवर्नेंस मॉडल अपनाया है। निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को सुविधा देने, नई तकनीक अपनाने और वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार पहल कर रही है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान की यात्रा पर आया है ताकि संभावनाओं को अवसर में बदला जा सके।

यामानाशी से गहरे होते संबंध

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यामानाशी प्रांत के राज्यपाल एवं उनकी टीम के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जापान सरकार और यामानाशी प्रशासन ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को उनके विशिष्ट क्षेत्रों को नजदीक से समझने और उद्योग जगत से सीधे संवाद का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है।

तकनीक और भविष्य के क्षेत्रों पर जोर

मुख्यमंत्री ने रोबोटिक्स को भविष्य की प्रमुख तकनीक बताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की व्यवस्था की है। संबंधों को नई ऊंचाई तक ले जाएगा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा तकनीक को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मियां मुसलमान विवाद पर असम सीएम को हाइकोर्ट का नोटिस

याचिका में हिमंता को हेट स्पीच देने से रोकने की मांग की गई थी

तमसा संकेत, एजेंसी

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के मियां मुसलामान वाले बयान पर गुवाहाटी हाइकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। ये नोटिस राज्य में माइनॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ हेट स्पीच देने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया गया। याचिका में कहा गया था कि CM सरमा के हेट स्पीच के वीडियो वायरल होने के बावजूद, असम पुलिस ने खुद से FIR दर्ज नहीं की है। इसमें दावा किया गया है कि CM के खिलाफ कार्रवाई न करने से सजा से बचने का माहौल और डरावना असर होता है। असमिया स्कॉलर

डॉ. हिरेन गोहेन और दो अन्य लोगों ने इसे दायर किया था। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचे पिटीशनर्स से कहा था कि वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। एक पिटीशनर की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस व्यक्ति के काम की एक जैसी, लगातार और आदतन प्रकृति को देखिए।

कोर्ट ने केंद्र और असम डीजीपी को भी नोटिस भेजा

मामले की सुनवाई के बाद, चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार, असम सरकार, असम डायरेकेटर जनरल ऑफ पुलिस(DGP) और मुख्यमंत्री को नोटिस जाकी किया। कोर्ट ने अंतरिम राहत की अर्जी पर भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं है। सेक्युलरिज्म और भाईचारे का उल्लंघन किया

यह इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं: राहुल

शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा, यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर पीएम मोदी की आलोचना की

आलोचना

"राहुल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी की आत्मा है। यह कोई अपराध नहीं है। उन्होंने पूछा... जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए, तो उन पर भी शक की नजर डाली गई। यह कैसा लोकतंत्र है, जहां ढट सवालों से डरते है? जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है?

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को यूथ कांग्रेस मेंबर्स के खिलाफ एक्शन पर राहुल ने PM मोदी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि PM मोदी की सरकार और नॉर्थ कोरिया के तानाशाही शासन एक जैसा है। ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं। दरअसल, दिल्ली में आयोजित AI समिट के दौरान यूथ कांग्रेस मेंबर्स ने शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट किया था। इस संबंध में दिल्ली पुलिस 3 सदस्यों को गिरफ्तार करने शिमला पहुंची थी। इसके बाद हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को उन्हें ले जाने से रोक लिया था। राहुल ने ये बातें गिरफ्तार तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिल्ली वापस लाने की इजाजत मिलने के बाद कही। दिल्ली में AI समिट में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने

के आरोप में 3 यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को हिमाचल और दिल्ली पुलिस में टकराव हो गया। दिल्ली पुलिस ने शिमला के एक होटल से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 3 नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन हिमाचल पुलिस ने उन्हें आधे रास्ते में रोक लिया और दिल्ली नहीं ले जाने दिया। हिमाचल पुलिस का तर्क था कि इस बारे में दिल्ली पुलिस ने कोई औपचारिक सूचना नहीं दी। हिमाचल में सादे कपड़ों में आकर मेहमानों को उठाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी दोनों पुलिस में बहस होती रही। इसके बाद जज ने फाइल तैयार करने को कहा तो दिल्ली पुलिस फिर बिना कागजी कार्रवाई के तीनों नेताओं को ले गई। इसका पता चलते ही हिमाचल पुलिस ने फिर उन्हें रोक लिया। इसके बाद तीनों नेताओं को कोर्ट में पेश कर दिल्ली पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पर लिया। करीब 18 घंटे तक दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच ड्रामा चलता रहा।

फास्ट न्यूज

मौत से पहले मां को लिखा- आई लव यू

हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में 21 साल की यूट्यूबर अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स से मुताबिक, मौत से कुछ घंटे पहले उसने अपनी मां को 'आई लव यू मम्मी' का मैसेज भेजा था। मृतका की पहचान बोनू कोमली के रूप में हुई है। वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की रहने वाली थी। करीब 11 महीने से हैदराबाद में रहकर एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी की पढ़ाई कर रही थी।

संबित पात्रा ने नेहरू को 'कंप्रोमाइज्ड चाचा' बताया

नई दिल्ली। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू का कंप्रोमाइज्ड चाचा बताया। पात्रा ने कहा कि मैं बताता हूं कि असली समझौता किसने किया। इस सिलसिले में नेहरू का नाम सबसे पहले आता है। पात्रा ने कहा कि नेहरू के निजी सचिव रहे एम.ओ. माथाई को लेकर कहा जाता था कि वे अमेरिकी एजेंट थे। 1960 के दशक में सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच रखते थे।पात्रा बोले- उस दौर में यह चर्चा आम थी कि विदेशी एजेंसियों को जो भी संवेदनशील दस्तावेज चाहिए होते थे, वे आसानी से मिल जाते थे। संबित पात्रा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कहीं।

भाजपा ने उमर खालिद से राहुल गांधी की तुलना की

नई दिल्ली। दिल्ली में एआई समिट में हुए हंगामे पर भाजपा ने एक बार फिर राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। भाजपा ने राहुल गांधी की तुलना 2020 दंगे के आरोपी उमर खालिद से करते हुए दिल्ली भाजपा ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया। जिसमें लिखा- अराजकता का तरीका एक, बस देश विरोधी चेहरे बदलते रहते हैं। इस पोस्टर में एक तरफ उमर खालिद हैं जिसमें उसे CAA के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट का सैनिकों के हक में फैसला

कहा- लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बताकर दिव्यांगता पेंशन नहीं रोक सकते

फैसला

तमसा संकेत, एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सशस्त्र बलों के कर्मियों की दिव्यांगता पेंशन को सिर्फ यह कहकर नहीं रोका जा सकता कि बीमारी 'लाइफस्टाइल डिसऑर्डर' है या वह पीस एरिया में तैनाती के दौरान हुई। हाई कोर्ट ने कहा कि गैर-ऑपरेशनल क्षेत्रों में भी सैन्य सेवा तनावपूर्ण होती है और इससे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बता दें कि सेना में 'पीस पोस्टिंग' का मतलब है कि सैनिक या अधिकारी की पोस्टिंग बॉर्डर पर नहीं बल्कि शांत और सुरक्षित शहरों या छावनियों में होती है।

>> (शेष पेज 04 पर)

कोर्ट ने साफ कहा कि यह मायने नहीं रखता कि बीमारी फील्ड एरिया में हुई या पीस पोस्टिंग में। असली सवाल यह है कि क्या बीमारी का सेवा परिस्थितियों से संबंध है। इस केस में रिलीज मेडिकल बोर्ड यह ठीक से नहीं बता सका कि अफसर की बीमारियां सेवा से जुड़ी नहीं थीं या सेवा के कारण नहीं बढ़ीं।

मोदी बोले- जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, इजराइल आना मेरे लिए गर्व की बात

भारतीय यूपीआई चलेगा, मोदी-नेतन्याहू की बैठक में समझौता

तमसा संकेत, एजेंसी

तेल अवीव। प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल दौरे का आज आखिरी दिन हैं। मोदी दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले यरूशलम के होलोकॉस्ट मेमोरियल 'याद वाशेम' पहुंचे। यहां उन्होंने हिटलर के नाजी शासन में मारे गए 60 लाख यहूदियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद इजराइली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात की। इस दौरान इसाक ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। वहीं, पीएम मोदी ने इजराइली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता दिया। फिर पीएम मोदी और इजराइली पीएम नेतन्याहू ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया गया है कि इजराइल में भी अब भारत का UPI पेमेंट सिस्टम चलेगा। PM मोदी ने कहा कि भारत जल्द इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) करेगा। मोदी बुधवार को इजराइल पहुंचे थे। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर मोदी को रिसीव किया था। इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइली संसद नेसेट को भी संबोधित किया। उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान 'स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल' दिया गया। मोदी नेसेट को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी थी।

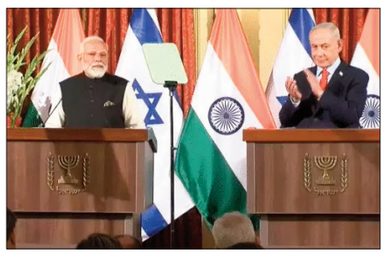

>> (शेष पेज 04 पर)

भारत-इजराइल में एफटीए पर बातचीत का पहला दौर पूरा

भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत का पहला दौर पूरा हो गया है। यह 23 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू हुआ था और यह 26 फरवरी 2026 तक चला। नवंबर 2025 में दोनों देशों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर साइन किए थे, जिससे यह तय हुआ कि किन मुद्दों पर बातचीत होगी और कैसे आगे बढ़ा जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच कुल सामान का व्यापार 3.62 अरब अमेरिकी डॉलर यानी करीब 31 हजार करोड़ रुपए रहा। दोनों देश कई क्षेत्रों में एक-दूसरे के लिए फायदेमंद हैं।

इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के एक्सपर्ट्स अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इनमें गुड्स एंड सर्विसेज का व्यापार, रूल्स ऑफ ओरिजन, हेल्थ और पौधों से जुड़े नियम, व्यापार में आने वाली तकनीकी रुकावटें, कस्टम प्रोसेस, व्यापार को आसान बनाने के उपाय और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे मुद्दे शामिल हैं।

हिटलर के शासन में मारे गए यहूदियों की याद में बना 'यद वाशेम' स्मारक

याद वाशेम होलोकॉस्ट के दौरान मारे गए लाखों यहूदियों की याद में बनाया गया है। यह स्मारक इजराइल की राजधानी यरुशलम में स्थित है और हर साल दुनिया भर से लोग यहां आकर इतिहास को समझते हैं।

आरोप : लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान 2027 चुनाव के लिए सतर्क रहने की अपील

भाजपा को हराना ही यूपी को बचाना : अखिलेश

तमसा संकेत, संवाददाता

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना जरूरी है, क्योंकि भाजपा को हराना ही प्रदेश को बचाने के समान है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार, अपराध और कमीशनखोरी की ओर धकेल दिया है और हर वर्ग के लोगों को अपमानित किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की रणनीतियों से सतर्क रहना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और इसमें कार्यकर्ताओं को पूरी समझदारी और

सावधानी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथित साजिशों से बचने के लिए संगठन को मजबूत करना होगा और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना होगा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं।

>> (शेष पेज 04 पर)

समाजवादी पार्टी की उपलब्धियों का किया उल्लेख

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में प्रदेश में कई विकास कार्य किए थे। उन्होंने छात्र-नौजवानों को लैपटॉप वितरण योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे युवाओं को तकनीकी रूप से आगे बढ़ने और नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने, बेरोजगारी समाप्त करने और मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इन मुद्दों पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाएगा।

कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल, बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई।

करप्शन इन ज्यूडीशियरी' वाली एनसीईआरटी किताब पर एससी का बैन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' चैप्टर वाली NCERT के 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब बैन कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने किताब छापने और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि जो किताबें छप चुकी हैं, उसे जब्त कीजिए और डिजिटल कॉपियों को भी हटाइए। कोर्ट ने इस मामले में NCERT डायरेक्टर और केंद्रीय शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिलेबस से जुड़ी बैठकों की कार्यवाही और विवादित चैप्टर लिखने वाले लेखकों के नाम और उनकी योग्यता बताने को भी कहा है। CJI ने कहा- यह न्यायपालिका को बदनाम करने की गहरी और सोची-समझी साजिश लगती है। जिम्मेदारों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विवादित चैप्टर को तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है।

सूरत की आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी में हंगामा

वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे कर्मचारियों ने की आगजनी

विरोध

तमसा संकेत, एजेंसी

सूरत। गुजरात के सूरत में हजीरा स्थित आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील कंपनी में गुरुवार सुबह हंगामा हो गया। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे कर्मचारी अचानक बिफर गए। उन्होंने 10 से ज्यादा गाड़ियों मे आग लगा दी। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया, जिसमें महिला डीसीपी घायल हो गईं। कंपनी के बन रहे नए प्लांट में आज सुबह 5000 से ज्यादा कर्मचारी अचानक काम छोड़कर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल की मुख्य वजह काम के घंटों में हुई बढ़ोतरी को कम करने और वेतन वृद्धि है। शुरुआत में हड़ताल शांति से हो रही थी। लेकिन अचानक कुछ कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर

दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल की एक बड़ी टुकड़ी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 40 से अधिक आंसू गैस के गोले दागे।पुलिस ने हिंसा में शामिल करीब 25 मजदूरों को हिरासत में लिया है। इस बारे में लार्सन एंड टुब्रो ने एक बयान जारी करते हुए कहा- गुजरात सरकार द्वारा श्रम संहिता की अधिसूचना लागू होते ही, हम इसके सभी नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। फिलहाल हम सभ कर्मचारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।

सम्पादकीय

अपने मूल उद्देश्य से भटक गया रेरा

जब भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 यानी रेरा के नौ साल पूरे हो चुके हैं, तब पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की ओर से उसके खिलाफ की गई सख्त टिप्पणी ने सबका ध्यान खींचा। इस कानून को इस उम्मीद में बनाया गया था कि इससे घर-फ्लैट खरीदारों को मदद मिलेगी और उन्हें बिल्डरों की मनमानी और भ्रष्टाचार से राहत मिलेगी, लेकिन हो रहा उलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेरा को बंद कर देना ही बेहतर है, क्योंकि यह डिफाल्टर बिल्डरों को फायदा पहुंचा रहा है और रिटायर्ड आइएएस अधिकारियों का पुनर्वास केंद्र बन गया है। अब समय आ गया है कि राज्य सरकारें रेरा के गठन पर दोबारा विचार करें।

संसद ने रेरा इसलिए बनाया था, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर में अनुशासन, पारदर्शिता आए और लोगों का भरोसा बने। उपभोक्ता कानून की तरह सिर्फ नुकसान होने के बाद मुआवजा देना इसका उद्देश्य नहीं था।

रेरा को इस तरह बनाया गया था कि वह नुकसान होने से पहले ही उसे रोके। यानी लगातार निगरानी और सख्त कार्रवाई इसकी असली ताकत थी। सवाल यह है कि क्या इसे सही तरीके से लागू किया गया? अगर रेरा के प्रविधानों को सख्ती से लागू किया जाता और पंजीकरण के समय बिल्डरों की पूरी और गंभीर जांच होती तो अधिकतर प्रोजेक्ट समय पर और बिना किसी शिकायत के पूरे होते। ऐसी स्थिति में बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरा करना अपनी प्रतिष्ठा का विषय बनाते। सही तरीके से लागू किया गया कानून सिर्फ सजा नहीं देता। वह ऐसी व्यवस्था बनाता है, जहां अच्छा प्रदर्शन दिखे भी और उसे मापा भी जा सके।

समय पर और बिना विवाद के प्रोजेक्ट पूरा होने पर ही "रेरा है तो भरोसा है" जैसे नारे सच में भरोसा पैदा करते, सिर्फ नारा बनकर नहीं रह जाते, लेकिन हकीकत यह है कि पंजीकरण सिर्फ कागज अपलोड करने की प्रक्रिया बनकर रह गई है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां बिल्डर के ब्रोशर में देशभर में कई परियोजनाएं दिखाई गईं, लेकिन रेरा पोर्टल पर केवल एक ही पंजीकृत परियोजना दर्ज थी और शिकायतों का डाटा भी बहुत कम था। जब प्रोजेक्ट की सुविधाओं की जानकारी बिल्डर की वेबसाइट, स्वीकृत नक्शों और रेरा पोर्टल पर अलग-अलग दर्ज हो तो फिर कोई घर-खरीदार प्रोजेक्ट के बारे में सही और सटीक जानकारी कहां से हासिल करे? यदि जानकारी ही स्पष्ट न हो तो रेरा के वेब पोर्टल का घर-खरीदार को वास्तविक लाभ क्या मिला? बिक्री समझौते का मसौदा भी कई बार उपलब्ध नहीं होता, जिसे कानून के तहत अनिवार्य रूप से रेरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। यह दिखाता है कि परियोजनाओं का पंजीकरण ठीक से नहीं किया जा रहा है और शुरुआत में ही सही जांच नहीं हो रही है। रेरा कहता है कि प्रोजेक्ट की समय सीमा बढ़ाना सिर्फ खास परिस्थितियों में होना चाहिए, लेकिन कई राज्यों में एक्सटेंशन आम बात है। एक्सटेंशन मिलने के बाद भी सभी खरीदारों को अपने-आप मुआवजा मिलना शुरू नहीं होता। आम तौर पर देरी का कोई सीधा आर्थिक असर बिल्डर पर नहीं पड़ता, लेकिन घर-खरीदार के लिए देरी बहुत ही महंगी पड़ती है। कायदे से यह बिल्डर को भी महंगी पड़नी चाहिए।

आज डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। प्राधिकरण चाहें तो निर्माण की वास्तविक प्रगति की तुलना रिपोर्ट से कर सकते हैं, पैसों के प्रवाह को देख सकते हैं, जोखिम पहले से पहचान सकते हैं और भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी विलंब या विवाद को पहले ही पकड़ सकते हैं और समय रहते सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं, लेकिन इस रोकथाम पर उनका ध्यान ही नहीं है जो कानून का मुख्य उद्देश्य है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (महारेरा) की वेबसाइट पर उपलब्ध एक बिक्री समझौते में लिखा है कि अगर खरीदार 15 दिनों में कब्जा नहीं लेता तो 40 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह होल्डिंग चार्ज देना होगा। 1,000 वर्ग फुट के फ्लैट पर यह 40,000 रुपये प्रति माह बनता है। कानून खरीदार को कब्जा लेने के लिए 60 दिन देता है। नियमों में भी कहा गया है कि देरी की स्थिति में मुख्यतः मेंटेनेंस चार्ज देय होगा। फिर भी ऐसे प्रविधान खुलेआम बिल्डरों द्वारा डाले जा रहे हैं।

जब बिल्डर खुद देरी करता है तो खरीदार के लिए "अन-होल्डिंग चार्ज" जैसा कोई प्रविधान नहीं है, जबकि खरीदार को एक साथ ईएमआइ और किराया देना पड़ता है। लगता है बिल्डर मानकर चल रहे हैं कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। कोई कानून तभी काम करता है, जब नियम तोड़ना महंगा हो। अगर नियम तोड़ना सस्ता पड़े तो अनुशासन खत्म हो जाता है। जब नियम मानना वैकल्पिक लगे और नियम तोड़ने पर कोई खास नुकसान जब नियम मानना वैकल्पिक लगे और नियम तोड़ने पर कोई खास नुकसान न हो तो कानून अपना असर खो देता है।

देश की राजधानी दिल्ली बनी गुमशुदगी का हॉटस्पॉट हर एक घंटे दो इंसान हो रहे गायब

"दिल्ली तो दिल्ली इस तरह की भयावह तस्वीर झारखंड से भी सामने आ रही है। यहां से भी बड़ी संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं। बच्चे कहां गायब हो रहे है। क्यूं गायब हो रहे है। इसका संतुष्टिजनक जवाब किसी के पास नही है। झारखंड में ऐसे अनेक परिवार हैं जिनके लडक़े-लड़कियां निजी प्लेसमेंट एजेंसियों या बाहर काम दिलाने वाले कथित एजेंटों के बहकावे में आकर अपने परिवार से दूर हो गए है।

दिल्ली देश की राजधानी है। हमारे देश का चौकीदार भी इसी शहर में रहता है। जिस शहर में किसी देश का चौकीदार निवासरत हो वो भी राष्ट्रवादी विचारधारा से सराबोर, ऐसे चौकीदार के राज में तो दिल्ली का क्या पर देश के हर अंचल का नागरिक खुद को महफूज समझेगा। सुरक्षित मानेगा। पर जनाब ऐसा हरगिज नहीं है। हमारे इस चौकीदार की छत्रछाया में दिल्ली तो क्या, हर राज्य का इंसान खासकर जवान लड़कियां और महिलाएं किसी भी कीमत पर सुरक्षित नहीं है। अब आप कहेंगे ये तो कोई बात नही हुई। इतने कर्मशील और महान प्रधान सेवक के राज में क्या किसी प्रकार से कानूनी अराजकता का बोलबाला हो सकता है। गर ये बात किसी अंधभक्त से पूछी जाएगी तो यकीनन नहीं । बहरहाल, इस मामले मैं आपको दिल्ली के कुछ आंकड़ों से रूबरू कराता हूं। ये वही डरावने और भयावह आंकड़ें है जो हमारे चौकीदार की नागरिक सुरक्षा की तमाम बड़ी- बड़ी बातों को खुलेआम धत्ता बताते है। आप इन आंकड़ों को सच माने या न माने लेकिन हमारे चौकीदार की नाक के नीचे दिल्ली जैसे शहर से हर एक घंटे में दो लोग गायब हो रहे है। इसके चलते दिल्ली इस समय गुमशुदगी का हॉटस्पॉट बन गई है। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच दिल्ली से कुल 807 लोग लापता हो चुके है। लापताओं में 509 महिलाएं है जबकि इन लापताओं में एक-तिहाई नाबालिग हैं। क्या आपको नही लगता है कि साल 2026 के शुरुआती पंद्रह दिन के अंदर ही 800 से अधिक इंसानों का लापता हो जाना न केवल चौंकाने वाली बात है बल्कि, यह राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता भी पैदा करती है। ये स्थिति हर उस शहर के लिए गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां पहले से ही कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ढुलमुल रवैया रहा है। गुमशुदगी के ये जो आंकड़े सामने आए है इनका मतलब साफ

है, हर दिन औसतन 54 दिल्लीवासी करीब- करीब हर घंटे में दो लोग गायब हो रहे हैं। गायब होने वालों में महिलाओं और बच्चों की बढ़ती संख्या ने मानव तस्करी, अपहरण और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े संकटों की आशंका को गहरा दिया है। सच कहें तो ये आंकड़े केवल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा भर नहीं हैं बल्कि सैकड़ों परिवारों का रूदन है। अपनों के बिछडने का असहनीय दर्द है। समाज में बढ़ती अराजकता और असुरक्षा की परतों का खुलासा है। गर हम दिल्ली पुलिस की दलील को माने तो 807 लापता में 191 नाबालिग हैं। इनमें 146 लड़कियां और 45 लडक़े हैं। पुलिस के अनुसार इन मामलों में करीब 71 प्रतिशत का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। आठ से बारह वर्ष की उम्र के 13 बच्चे और आठ वर्ष से कम उम्र के 9 बच्चे भी 1 से 15 जनवरी 2026 के बीच लापता हुए हैं। अब तक केवल 235 लोगों का ही पता लगाया जा सका है जबकि 3 फरवरी तक 572 लोग ऐसे थे जिनके बारे में पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। दिल्ली से लोगों के गायब होने का ये जो सिलसिला बना हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानसेवक की भारत के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर जुमलेबाजी को ही दर्शाते है। ये आकड़े दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नाकामयाबी का भी आईना है। आंकड़ें इन दोनों जिम्मेदारों की अगंभीरता को ही उजागर करते है। पहले इस काम में रांची, खूंटी, गुमला जैसे जिलों के बच्चे निशाने पर होते थे, अब यह सिंहभूम और संथाल जैसे इलाके में शिफ्ट हो गया है। इस इलाके की पहाडिय़ा, संथाली आदिवासी लड़कियों का बाहर जाना और फिर वापस लौट कर नहीं आना, आम बात हो गई है। दरअसल, गुमशुदगी का ये आलम दिल्ली और झारखंड तक ही सीमित नही है बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी बड़ी संख्या में युवतियां, महिलाएं, बच्चे और पुरूष लापता हो रहे है। देश के कौन- कौन से राज्यों से कितने लोग गायब हो रहे है, इनके आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो याने एनसीआरबी की सालाना रिर्पोट से मिलते रहते है। सनद रहे कि दिल्ली और झारखंड से लापता लोगों की समस्या अनेक वर्षों से चिंता का सबब बनी हुई है। दिल्ली से बीते साल यानी 2025 में कुल 24,508 लोग लापता हुए थे। इनमें 14,870 यानी 60 फीसदी से अधिक महिलाएं थी। वर्ष 2024 में लापता नाबालिगों की संख्या 5,846 थी जबकि 2023 में यह आंकड़ा 6,284 था। बीते दस वर्षों में दिल्ली से करीब 2. 51 लाख लोग गायब हो चुके है जबकि करीब 52,000 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका है। इधर, झारखंड में साल 2024 में कुल 282 लोग तस्करी के शिकार हो चुके है। इनमें 18 साल से कम उम्र के 163 लडक़े है और 53 लड़कियां शामिल हैं। यहां से 2025 में अप्रैल तक कुल 64 नाबालिग तस्करी के शिकार हो चुके हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2023 में पूरे भारत में करीब 8.68 लाख लोग लापता हुए थे। 2023 की रिपोर्ट की माने तो भारत में लापता महिलाओं में से करीब 20 से 25 प्रतिशत महिलाएं मानव तस्करी का शिकार होती हैं। दिल्ली में प्रवासी आबादी बड़ी संख्या में रहती है और इन्हीं समुदायों से गुमशुदगी के मामले अधिक दर्ज होते है। पुलिस अफसरों के अनुसार नेपाल और बांग्लादेश से जुड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क दिल्ली और झारखंड़ को अपना हब बनाते हैं। रिपोर्ट में इस बात को भी साफ जाहिर किया गया कि दिल्ली जैसे बड़े शहरी केंद्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है। बीती 3 जुलाई को तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस को नाबालिग बच्चियों का एक झुंड दिखा था। इनमें पांच नाबालिग झारखंड की थी। ये सब एक स्थानीय दलाल के संपर्क में आईं थी, जिसने इन्हें सेलम में काम दिलाने का वादा किया था। तब पुलिस ने उन्हें स्थानीय शेल्टर होम को सौंप दिया था और बीते 9 सितंबर को सभी को वापस झारखंड़ भेज दिया था अब लाख टके का सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे गायब कैसे हो रहे है। क्यों इतने लोग लापता हो रहे है।

संजय रोकड़े

जन सुराज का...

ललित गर्ग

शिक्षा को हिंसक नहीं, संवेदनशील बनाना होगा

देश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। हर साल की तरह इस बार भी परीक्षा का मौसम केवल प्रश्नपत्रों और परिणामों का नहीं, बल्कि मानसिक दबाव, चिंता और असुरक्षा का मौसम बनता जा रहा है। छात्रों के चेहरों पर भविष्य की चिंता साफ पढ़ी जा सकती है। यह चिंता केवल अच्छे अंक लाने की नहीं, बल्कि अपेक्षाओं के बोझ को ढोने की है। दुर्भाग्य यह है कि यह दबाव कई बार इतना असहनीय हो जाता है कि वह आत्मघाती या हिंसक रूप ले लेता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े एक भयावह सच उजागर करते हैं। वर्ष 2013 से 2023 के बीच छात्रों की आत्महत्या की दर में लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि हजारों परिवारों के टूटने की कहानी है। इन आत्महत्याओं के पीछे पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक अपेक्षाएं, सामाजिक तुलना और आर्थिक तनाव प्रमुख कारण बताए जाते हैं। लेकिन हाल में लखनऊ में जो घटना सामने आई, उसने इस संकट को एक और खतरनाक दिशा में मोड़ दिया है। लखनऊ की घटना केवल परीक्षा दबाव की कहानी नहीं है, बल्कि परिवारों में बढ़ती संवेदनहीनता, संवाद-हीनता और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा का दर्पण है। पुलिस जांच के अनुसार एक पैथोलॉजी लैब संचालक पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते थे और उस पर नीट जैसी परीक्षा पास करने का लगातार दबाव बना रहे थे। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच बहस हुई और 21 वर्षीय युवक ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपराध छिपाने के लिए शव के टुकड़े किए, कुछ बाहर फेंके, कुछ घर में छिपाए, छोटी बहन को धमकाया और पुलिस को गुमराह करने के लिए पहले लापता होने और फिर आत्महत्या की कहानी गढ़ी। यह सब बताता है कि यह क्षणिक आवेश नहीं था, बल्कि भीतर लंबे समय से पल रही कुंठा, आक्रोश और मानसिक विघटन का परिणाम था। प्रश्न यह है कि एक बेटे के भीतर इतनी नफरत कैसे पनप सकती है? क्या 'कुछ बनने' का दबाव इतना भारी हो सकता है कि वह रिश्तों को भी तार-तार कर दे? हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सफल हो, प्रतिष्ठित करियर बनाए, समाज में सम्मान पाए। लेकिन जब यह चाहत संवाद और सहयोग की जगह नियंत्रण और दबाव का रूप ले लेती है, तब वह प्रेरणा नहीं, मानसिक उत्पीड़न बन जाती है। जब शिक्षा जीवन-निर्माण का माध्यम न होकर, विनाश का कारण बन जाती है। भारत में नीट और जी जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों युवाओं के लिए उम्मीद का प्रतीक हैं। नीट में पिछले वर्ष 23 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया, जबकि ज्वाइंट एन्टरेंस एक्जामिनेशन (जेईई) के एक सत्र में 13 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया। इन लाखों विद्यार्थियों में से केवल कुछ हजार ही शीर्ष संस्थानों तक पहुंच पाते हैं। शेष विद्यार्थियों के हिस्से अक्सर निराशा, आत्मग्लानि और सामाजिक तुलना का दंश आता है। जब सफलता का पैमाना केवल रैंक और अंक बन जाए, तो असफलता जीवन का अंत प्रतीत होने लगती है। कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में हर वर्ष आत्महत्या की खबरें सामने आती हैं। कोटा देश की कोचिंग राजधानी कही जाती है, जहां हजारों छात्र सपने लेकर पहुंचते हैं। लेकिन उन्हीं सपनों का बोझ कई बार उनके जीवन से भारी पड़ जाता है। यह केवल व्यक्तिगत कमजोरी का मामला नहीं है, बल्कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का परिणाम है जिसमें प्रतियोगिता सहयोग से अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है। लखनऊ की घटना में एक और तथ्य उल्लेखनीय है- आरोपी छात्र की मां का निधन हो चुका था। घर में चाचा-चाची मौजूद थे, लेकिन क्या उस युवक की मनःस्थिति को समझने का प्रयास किया गया? क्या उसके भीतर के तनाव, अकेलेपन और भय को किसी ने सुना? यदि परिवार में नियमित संवाद होता, यदि मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही गंभीरता से लिया जाता जितनी अंकों को, तो शायद यह भयावह वारदात टाली जा सकती थी। आज समस्या केवल आत्महत्या तक सीमित नहीं है। बच्चे हिंसक भी हो रहे हैं। यह हिंसा बाहरी नहीं, भीतर से उपज रही है-कुंठा, अपमानबोध, तुलना और असफलता के भय से। जब बच्चे को यह महसूस होने लगे कि वह केवल एक 'प्रोजेक्ट' है।

सरकारी जमीन...

राजेश कुमार पासी

सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश

हल्द्वानी में अतिक्रमण का मामला बहुत जटिल है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जैसा स्पष्ट रुख अपनाया है, उससे पूरे देश में एक सकारात्मक संदेश गया है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण देश की बहुत बड़ी समस्या है लेकिन अदालतों के कारण इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वास्तव में जब भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की जाती है तो अदालतें इस पर रोक लगा देती हैं। ज्यादातर मामलों में यही दलील दी जाती है कि वर्षों तक रहने वाले लोगों को उजाड़ना मानवीय दृष्टि से सही नहीं है। अतिक्रमणकारियों को अदालतों, राजनीतिक दलों और एनजीओ का साथ मिल जाता है, इसलिए उनका हौसला बढ़ा हुआ है। देखा जाए तो पूरे देश में लाखो एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण का शिकार है। विशेष रूप से रेल की पटरियों और सड़कों के आसपास की खाली जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है। समस्या यह है कि जब सरकारी जमीन पर कब्जा शुरू होता है तो सरकारी विभाग आंख बंद करके बैठे रहते हैं। जब धीरे-धीरे वहां बसावट हो जाती है तो वोट के लालच में राजनीतिक दल वहां सारी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा देते हैं। ज्यादातर मामलों में सत्ताधारी दल के नेता इन लोगों को वोट बैंक के रूप में देखते हैं और इनका संरक्षण करते हैं। अगर संबंधित विभाग अपनी जमीन खाली भी करवाना चाहे तो ये नेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मामले को लटका देते हैं। अगर विभाग अदालत चला जाए तो वहां मामला वर्षों तक लटका रहता है। अतिक्रमणकारी अदालत में दलील देते हैं कि वो गरीब लोग हैं. अगर उन्हें हटाया जाता है तो वो सड़क पर आ जाएंगे, इसलिए उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जाए। कितनी अजीब बात है कि ये लोग पहले जबरन कब्जा करके वर्षों

तक सरकारी जमीन का इस्तेमाल करते हैं और जब उन्हें हटाया जाता है तो उन्हें मुआवजा और पुनर्वास भी चाहिए। देखा जाए तो वर्षों तक सरकारी जमीन का इस्तेमाल करने की एवज में इनसे किराया वसूला जाना चाहिए। दूसरी बात , जो अफसर और नेता अतिक्रमण के लिये जिम्मेदार होते हैं, उनसे राजस्व हानि की भरपाई की जानी चाहिए। सरकारी जमीन पर कब्जे के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस सवाल का जवाब हर अतिक्रमण के लिए पूछा जाना चाहिए कि जब कब्जा हो रहा था तो उसे उस समय ही क्यों नहीं रोक दिया गया। हल्द्वानी का अतिक्रमण भी अफसरों और नेताओं की मिलीभगत का नमूना है। रेलवे की 31 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा करके 5000 परिवार वहां बस गए हैं। कब्जा की गई जमीन पर लगभग 50000 की आबादी रहती है। उनका दावा है कि वो लोग यहां 45-50 साल से रह रहे हैं। ये सवाल तो उठता है कि 31 हेक्टेयर जमीन पर जब कब्जा हो रहा था तो रेलवे कहां सोया हुआ था। ये कब्जा एक-दो दिन में नहीं हुआ होगा. धीरे-धीरे लोगों ने वहां कच्चे मकान बनाये होंगे और फिर लोगों का आना बढ़ता गया होगा। कुछ वर्षों बाद लोगों ने वहां पक्के मकान बना लिए होंगे। आज वहां बड़े-बड़े भवन खड़े हुए हैं।

जरा हटके

सुप्रीम कोर्ट ने...

प्रो. महेश चंद गुप्ता

भारतः एआई में आम आदमी को मिलेगी कितनी जगह?

हाल में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का समापन हुआ है। यह केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का अंत नहीं है बल्कि यह भारत के लिए एक नई तकनीकी यात्रा की शुरुआत का संकेत है। आज जब पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भविष्य की धुरी मानकर आगे बढ़ रही है, भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वह इस दौड़ में पीछे नहीं रहेगा। यह संदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एआई तकनीक अब किसी एक देश, एक कंपनी या कुछ अमीर समाजों तक सीमित तकनीक नहीं रह गई है। एआई वह औजार बन चुका है जो शासन, अर्थ व्यवस्था, समाज और व्यक्ति सबके जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाला है। भारत एआई में आगे बढ़ना चाहता है पर सवाल यह है कि क्या देश एआई को केवल उपभोक्ता की तरह या फिर निर्माता और दिशा निर्देशक के रूप में अपनाएगा? समिट के उद्घाटन अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस दृष्टि को सामने रखा है, वह दरअसल आत्म निर्भर और समावेशी सोच का विस्तार है। मोदी ने कहा है कि एआई केवल अमीर देशों की तकनीक नहीं होनी चाहिए बल्कि 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' का माध्यम बनना चाहिए। मोदी का यह कथन मौजूदा वैश्विक तकनीकी विमर्श में भारत की अलग पहचान को रेखांकित करने वाला है। यह कथन सिर्फ एक राजनीतिक वक्तव्य नहीं है बल्कि उस ऐतिहासिक अनुभव का निचोड़ है जिसमें भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम, डिजिटल भुगतान और आधार जैसी पहचान प्रणाली हर बड़ी तकनीक को अंततः आम आदमी के जीवन से जोडने की कोशिश की है। वास्तविकता यह है कि एआई आज हर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। कृषि में फसल पूर्वानुमान से लेकर स्वास्थ्य में रोग पहचान तक, शिक्षा में व्यक्तिगत रूप से सीखने के मॉडल से लेकर यातायात प्रबंधन और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों तक हर जगह एआई की भूमिका बढ़ती जा रही है। दुनिया के विकसित और विकासशील देश इस तकनीक को अपने-अपने ढंग से साधने में जुटे हैं। ऐसे वैश्विक परिदृश्य में यदि भारत एआई टूल्स विकसित करने में पीछे रह जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से इसके लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ेगा। यह निर्भरता केवल तकनीकी नहीं होगी बल्कि नीतिगत और रणनीतिक भी होगी। ऐसे में एआई इम्पैक्ट समिट भारत के लिए एक रोडमैप की तरह उभरा है। इस आयोजन ने ऐसा रोडमैप बनाया है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस दिशा में और किस गति से आगे बढना है। हालांकि किसी भी बड़े तकनीकी सपने की असली परीक्षा उसकी धरातल पर उतरने की क्षमता में होती है। सरकार की ओर से एआई को लेकर जो पहलें सामने आ रही हैं, उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अनुसंधान, स्टार्टअप्स, कौशल विकास और नीति निर्माण सभी स्तरों पर प्रयास दिखाई देते हैं लेकिन भारतीय व्यवस्था का एक कड़वा सच यह भी है कि अक्सर योजनाओं का लाभ अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही कुछ 'लपके' लोग बीच में समेट लेते हैं। एआई जैसी जटिल और शक्तिशाली तकनीक के साथ यह खतरा और भी बढ़ जाता है। यदि एआई का लाभ केवल बड़े शहरों, बड़ी कंपनियों और सीमित तबकों तक सिमट गया तो इसका उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए अब आवश्यकता इस बात की है कि एआई विशेषज्ञ, नीति निर्माता, मंत्रालय और नौकरशाही मिलकर इस बात पर गंभीरता से विचार करें कि आम आदमी को इससे सीधे कैसे जोड़ा जाए। आम आदमी को इसका प्रत्यक्ष लाभ कैसे मिले। उदाहरण के तौर पर यदि एआई के जरिये यह पता चल सके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कहां अनाज खुर्दबुर्द हो रहा है तो यह तकनीक भूख के खिलाफ एक प्रभावी हथियार बन सकती है। यदि टीकाकरण या प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट का संकेत एआई पहले ही दे दे तो समय रहते हस्तक्षेप संभव है। यदि मौसम और भूगर्भीय डेटा के विश्लेषण से यह अनुमान लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा की आशंका है तो जान-माल की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन इन सभी संभावनाओं के साथ निगरानी और जवाबदेही का प्रश्न भी जुड़ा है। हमने देखा है कि योजनाएं कागज से धरातल तक आते-आते कैसे बदल जाती हैं? हमारे देश में नई तकनीक का स्वागत पूरे उत्साह से होता है लेकिन कुछ समय बाद वही तकनीक निगरानी और जवाबदेही के अभाव में अपनी धार खोने लगती है। एआई के क्षेत्र में यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। हमें न केवल यह देखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं बल्कि यह भी निगरानी रखनी होगी कि दुनिया क्या कर रही है और हम उससे क्या सीख सकते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आत्म मुग्धता के लिए कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही एआई के दुरुपयोग की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डीपफेक, डिजिटल जालसाजी, निजता का उल्लंघन और गलत सूचना आदि एआई के स्याह पहलू हैं। सरकार ने इन पर लगाम लगाने के लिए कुछ कदम उठाने की घोषणा की है, जो स्वागत योग्य है लेकिन यह काम आधे-अधूरे प्रयासों से नहीं चलेगा। इसके लिए मजबूत कानूनी ढांचा, तकनीकी समाधान और जन-जागरूकता की जरूरत होगी। एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर विपक्षी दलों ने आपत्तियां जताई हैं। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है पर यदि हर नई तकनीक और हर दीर्घकालिक सोच का विरोध केवल विरोध के लिए किया जाए तो देश का हित पीछे छूट जाता है। आजादी के बाद यदि बाँध, अंतरिक्ष कार्यक्रम, कम्प्यूटर क्रांति और डिजिटल ढांचा जैसे हर बड़े विकास कार्यों का विरोध किया जाता तो क्या देश की तस्वीर आज जैसी होती? मोदी का 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार हो सकता है।

6 बैटर्स ने 50+ स्कोर बनाए, कर्नाटक से प्रसिद्ध कृष्णा को 5 विकेट
रणजी ट्रॉफी-जम्मू-कश्मीर पहली पारी में 584 पर ऑलआउट

- कर्नाटक के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए।
- यावर हसन और शुभम पुंदीर (दाएं) के बीच दूसरे विकेट के लिए 139 रन की साझेदारी हुई।

हुबली। भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025–26 के फाइनल मुकाबले में जम्मू-कश्मीर क्रिकेट टीम ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 584 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला टीम के लिए बेहद सफल साबित हुआ। तीसरे दिन के पहले सत्र में टीम ऑलआउट हुई, लेकिन तब तक वह मैच में मजबूत स्थिति हासिल कर चुकी थी। कर्नाटक के लिए सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा ने की। उन्होंने बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके और जम्मू-कश्मीर की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई। विजयकुमार वैशाक, शिखर शेट्टी और श्रेयस गोपाल को एक-एक विकेट मिला।

तीसरे दिन जल्दी गिरे आखिरी विकेट, फिर भी स्कोर पहुंचा 584

जम्मू-कश्मीर ने तीसरे दिन 527 रन पर 6 विकेट के नुकसान से आगे खेलना शुरू किया। उम्मीद थी कि टीम 600 के पार पहुंच सकती है, लेकिन कर्नाटक के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी करते हुए केवल 57 रन के अंदर शेष चार विकेट गिरा दिए। इसके बावजूद 584 रन का स्कोर किसी भी फाइनल मुकाबले में बेहद मजबूत माना जाता है।

पहले दिन से ही जम्मू-कश्मीर का दबदबा

मैच के पहले दिन से ही जम्मू-कश्मीर ने कर्नाटक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। टीम ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना लिए थे। शुभम पुंदीर और यावर हसन की शानदार बल्लेबाजी ने कर्नाटक को बैकफुट पर धकेल दिया था।

ओपनर यावर हसन ने 88 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके अलावा अनुभवी बल्लेबाज पारस डोगरा और कन्हैया वधावन ने 70-70 रन बनाए। साहिल लोत्रा ने 72 रन का योगदान दिया, जबकि आक्रामक बल्लेबाज अब्दुल समद ने 60 रन बनाकर टीम के स्कोर को और मजबूत किया।

दूसरे दिन भी जारी रहा बल्लेबाजों का शानदार प्रदर्शन

दूसरे दिन जम्मू-कश्मीर ने अपनी मजबूत स्थिति को और बेहतर बनाया। दिन का खेल खत्म होने तक टीम 6 विकेट पर 527 रन बना चुकी थी। साहिल लोत्रा 57 रन और आबिद मुश्ताक 20 रन बनाकर नाबाद लौटे थे।

वॉकिंग क्रिकेट, खिलाड़ियों को मिल रहा 'बैजबॉल' का मजा

ब्रिटेन में 87 की उम्र तक के लोग खेल रहे, बैटर आउट होने के बाद भी खेलता रहता है

लंदन, एजेंसी

इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने एक बार 'बैजबॉल' को परिभाषित करते हुए कहा था कि यह खेल को वैसे खेलने की कोशिश है, जैसा हमने बचपन में कल्पना की थी- रोमांचक, तेज और मजेदार। दिलचस्प बात यह है कि इस सोच की सबसे सजीव और भावुक झलक अब इंग्लैंड के लीजर सेंटरों और खेल के मैदानों पर दिख रही है, जहां 50 से 87 साल तक के लोग 'वॉकिंग क्रिकेट' के जरिए खेल का नया आनंद ले रहे हैं। वॉकिंग क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अकेलेपन के खिलाफ प्रभावी हथियार है। केंट क्रिकेट कम्युनिटी ट्रस्ट की प्रोजेक्ट ऑफिसर एमी इलिज के अनुसार, हर काउंटी में इसकी टीमें फल-फूल रही हैं। लॉर्ड्स के इंडोर स्कूल में पहला इंटर-काउंटी वॉकिंग क्रिकेट फेस्टिवल आयोजित हुआ, जिसने

इसकी बढ़ती लोकप्रियता पर मुहर लगा दी। केंट के फोकस्टोन स्थित श्री हिल्स स्पोर्ट्स सेंटर में वॉकिंग क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, सामुदायिक जुड़ाव का मंच बन चुका है। यहां 87 वर्ष तक के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। सुनने में दिक्कत, डिमेंशिया या गतिशीलता संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोग भी बिना झिझक मैदान में उतरते हैं। आधा रन लेने जैसी छूट इसे और रोचक बनाती है। इस खेल ने कई जिंदगियों को नई दिशा दी है। 62 वर्षीय कप्तान मार्क कहते हैं कि यहां प्रतिभा से ज्यादा भागीदारी और खुशी मायने रखती है। साल 2022 में दोनों घुटनों के ऑपरेशन के बाद ग्राहम दो स्टिक के सहारे चलते थे। वॉकिंग क्रिकेट से जुड़ने के महज 18 महीनों में उनका वजन एक-चौथाई कम हो गया और उन्होंने एक ओवर में छह छक्के जड़कर सबको हैरान कर दिया। सेना के दिनों में माल्टा के लिए खेल चुके जॉन कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद इस खेल ने उन्हें नई जिंदगी दी है। कई बार खिलाड़ियों को यह भी याद नहीं रहता कि मैच कौन जीता क्योंकि यहां जीत से ज्यादा मायने मुस्कान के हैं। - जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस खेल में दौड़ने की सख्त मनाही है। यह क्रिकेट का एक धीमा, सुरक्षित और सरल प्रारूप है, जिसे विशेष रूप से बुजुर्गों और चलने-फिरने में परेशानी (मोबिलिटी इश्यूज) का सामना कर रहे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है।

फास्ट न्यूज

सैमसंग गैलेक्सी एस26 सीरीज के 3 नए फोन लॉन्च

नई दिल्ली। सैमसंग ने अपनी सबसे पावरफुल 'गैलेक्सी S26' सीरीज लॉन्च कर दी है। 25 फरवरी को कैलिफोर्निया में हुए इवेंट में कंपनी ने तीन फोन और नई गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज पेश की। ये फोन दिखने में काफी हद तक पुरानी S25 सीरीज जैसे ही हैं, लेकिन इनके सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर में बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके टॉप वैरिएंट में दुनिया का पहला ऐसा प्राइवेसी फीचर दिया गया है।

सेंसेक्स मामूली गिरावट के साथ 82,249 बंद

मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी, 26 फरवरी को फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 27 अंक गिरकर 82,249 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 14 अंकों की गिरावट रही। ये 25,496 के स्तर पर बंद हुआ। आज के कारोबार में फार्मा और सरकारी बैंक के शेयरों में तेजी रही है। विदेशी निवेशकों (FII) ने 25 फरवरी को 2,991 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 5,118 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इस महीने यानी फरवरी में अब तक FIIs ने 4,361 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। इस दौरान DIIs ने 21,098 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। जनवरी 2026 में FIIs ने कुल 41,435 करोड़ के शेयर्स बेचे थे। इस दौरान DIIs ने 69,220 करोड़ के शेयर खरीदे थे। PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी के IPO का आज यानी 26 फरवरी को आखिरी दिन है।

1 मार्च से सिम कार्ड के बिना नहीं चलेगा वॉट्सएप

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 'सिम बाइंडिंग' के नियमों को लागू करने की 28 फरवरी की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। नए नियमों के तहत फोन में सिम कार्ड न होने पर वॉट्सएप जैसे मैसेजिंग एप काम नहीं करेंगे। कंप्यूटर पर लॉगिन वॉट्सएप भी 6 घंटे में लॉग-आउट हो जाएगा। जब आप किसी एप को सिम बाइंडिंग से जोड़ते हैं, तो वह एप तभी खुलेगा जब आपका रजिस्टर्ड सिम कार्ड उसी फोन के अंदर मौजूद होगा।

'भूत बंगला' का पहला गाना 'रामजी आके भला करेंगे' रिलीज

अक्षय कुमार क्लासिक कॉमिक अंदाज में नजर आए, गाने में हाई-एनर्जी विजुअल्स

नई दिल्ली, एजेंसी

फिल्म 'भूत बंगला' के पहले गाने 'राम जी आके भला करेंगे' को मेकर्स ने गुरुवार को रिलीज कर दिया। गाने में अक्षय कुमार अपने क्लासिक कॉमिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। वीडियो में हाई-एनर्जी विजुअल्स, भूतिया माहौल और तेज बीट्स देखने को मिलती हैं। बता दें कि गाने 'राम जी आके भला करेंगे' को प्रीतम ने कंपोज किया है, जबकि इसके लिरिक्स कुमार (राकेश कुमार पाल) ने लिखे हैं। गाने को अरमान मलिक और आरवन (देव अरिजीत) ने आवाज दी है। वहीं, मेलो डी द्वारा लिखा और परफॉर्म किया गया रैप सेगमेंट ट्रैक में कंटेम्परेरी टच जोड़ता है। गाने 'रामजी आके भला करेंगे' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फैंस अक्षय कुमार की क्लासिक कॉमिक एनर्जी और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ ने इसे "OG खिलाडी एनर्जी" कहा, तो कई दर्शकों ने

गाने को "चार्टबस्टर" करार दिया। यूट्यूब पर कमेंट्स में नॉस्टैल्जिया भी साफ झलक रहा है, जहां लोग प्रियदर्शन-अक्षय की पुरानी कॉमेडी फिल्मों को याद कर रहे हैं। हाई-एनर्जी बीट्स, फनी विजुअल्स और एंटरटेनमेंट फैक्टर को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। कुल मिलाकर, गाने को पॉजिटिव और एंगेजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है। गौरतलब है कि फिल्म 'भूत बंगला' को 2026 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में गिना जा रहा है। 14 साल बाद अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हिट जोड़ी बड़े पर्दे पर साथ लौट रही है।

'सलीम खान की तबीयत में सुधार हो रहा है'

आमिर खान ने हेल्थ अपडेट दी, दूसरी बार सलमान के पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे

नई दिल्ली, एजेंसी

सलमान खान के पिता और दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान की सेहत को लेकर आमिर खान ने कहा कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है और वे जल्द घर लौट सकते हैं। बुधवार को मुंबई प्रेस क्लब के कार्यक्रम में शामिल हुए आमिर खान से जब मीडिया ने सलीम खान की सेहत को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा, "मैं सलीम साहब से मिलने गया था। हम सब दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। क्योंकि वो ICU में थे, मैं उनसे पर्सनली नहीं मिल पाया। मैं उनके परिवार के साथ बैठा था। मुझे अलवीरा जी हर रोज बता रही हैं कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि वो एक बार फिर घर आ जाएं।"

आमिर खान दूसरी बार अस्पताल पहुंचे

वहीं, बुधवार देर शाम आमिर खान दूसरी बार लीलावती अस्पताल सलीम खान का हाल-चाल जानने पहुंचे। इससे पहले, आमिर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ 19 फरवरी को भी अस्पताल आए थे। गौरतलब है कि सलमान खान लगातार अस्पताल आ रहे हैं। बुधवार को भी उन्हें अस्पताल के बाहर देखा गया।

सलीम खान खतरे से बाहर: डेजी शाह

सलीम खान की सेहत को लेकर एक्ट्रेस डेजी शाह ने भी हाल ही में कहा था कि उनकी हालत में सुधार है। फिल्म जय हो में सलमान खान की को-स्टार डेजी शाह ने फिल्मीज्ञान से बातचीत में कहा, "मैं सलीम सर से मिल नहीं पाई, लेकिन सलमान सर और उनके परिवार के संपर्क में हूं। सलीम सर अब ठीक हैं। उनकी हालत स्थिर है। सर्जरी सफल रही। वह फिलहाल ऑब्जर्वेशन में हैं और खतरे से बाहर हैं।"

सलीम खान लीलावती अस्पताल में भर्ती

सलीम खान को 17 फरवरी को सुबह ब्रेन से जुड़ी दिक्कत के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सुबह करीब 8:30 बजे इमरजेंसी में लाया गया। शुरुआती जांच के बाद डॉक्टरों की एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसने उनकी स्थिति का आकलन किया।

बता दें कि 18 फरवरी को लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने सलीम खान की हेल्थ अपडेट दी थी। हालांकि, उस-के बाद परिवार की ओर से मेडिकल अपडेट सार्वजनिक न करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद उनकी हेल्थ को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट सामने नहीं आई।

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के निधन के बाद परिवार में तनाव की अफवाहों को किया खारिज
'फैमिली में कोई नेगेटिविटी नहीं है'

नई दिल्ली, एजेंसी

एक्टर धर्मेंद्र के निधन के बाद उनके परिवार में तनाव की चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए एक्ट्रेस और उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने कहा कि परिवार में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा, "पापा हैं ना। पापा के लिए हम सब कुछ करेंगे, चाहे ये बच्चे ईशा और अहाना हों या वो बच्चे सनी और बॉबी हों। सबको धरमजी से बहुत प्यार है और सब एक-दूसरे से भी बहुत प्यार करते हैं। परिवार में किसी तरह की कोई कड़वाहट नहीं है। जब धरमजी साथ हैं, तो नेगेटिविटी की कोई जगह ही नहीं है।" बता दें कि हाल ही में हेमा की दोनों बेटियां, ईशा और अहाना, सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की स्क्रीनिंग पर पहुंचीं और तीनों ने साथ में तस्वीरें भी क्लिक

करवाईं। हालांकि, फिल्म की स्क्रीनिंग में हेमा मालिनी शामिल नहीं हुईं, जिस पर भी उन्होंने अब प्रतिक्रिया दी है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। धर्मेंद्र के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में थे।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि वह धर्मेंद्र के साथ आखिरी बार स्क्रीन शेयर नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा, "हमने जो काम साथ किया, वही अब दर्शकों की यादें हैं। यह मानना मुश्किल है कि वह अब नहीं हैं।"

बीएएफटीए अवॉर्ड्स सेरेमनी में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई

बता दें कि 24 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र का निधन हुआ था। पिछले रविवार लंदन में आयोजित 79वें BAFTA अवॉर्ड्स के 'इन मेमोरियम' सेक्शन में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। इस साल इस सेक्शन में शामिल होने वाले वे एकमात्र भारतीय एक्टर थे। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए हेमा ने कहा, "यह बहुत खूबसूरत पल था। वह इसके हकदार थे। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। धर्मेंद्र के फैंस सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में थे।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि वह धर्मेंद्र के साथ आखिरी बार स्क्रीन शेयर नहीं कर पाईं। उन्होंने कहा, "हमने जो काम साथ किया, वही अब दर्शकों की यादें हैं। यह मानना मुश्किल है कि वह अब नहीं हैं।"

"हेमा मालिनी ने इस पर कहा, "धरमजी हमेशा प्यार, हिम्मत और अच्छे संस्कार देने वाले रहे हैं। वही सब उन्होंने बच्चों को दिया है। मुझे भी बुलाया गया था, लेकिन मैं जा नहीं पाई। सब चाहते थे कि मैं आकर फिल्म देखूं। हम हर बात को पब्लिक में दिखाते नहीं हैं और दिखाएं भी क्यों? ये सब हमारे परिवार की बातें हैं। लोगों को समझना चाहिए, यूं इधर-उधर की बातें नहीं करनी चाहिए।

बेटी के जन्म को याद कर इमोशनल हुईं प्रियंका

नई दिल्ली, एजेंसी

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सरोगेसी से जन्मी बेटी मालती मैरी के समय से पहले जन्म के समय को याद कर इमोनल हो गई। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि वह दौर उनके लिए निजी तौर पर बेहद मुश्किल और ट्रॉमेटिक था। उसी समय उन्हें एक मैसेज मिला कि मीडिया में बच्ची के जन्म की खबर आने वाली है। प्रियंका ने बताया कि वे सही समय पर खुद

यह खबर शेयर करना चाहते थे, लेकिन लीक के कारण उन्हें जल्दी में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उस वक्त वे तैयार नहीं थे, क्योंकि बच्ची की सेहत को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी 27 हफ्ते में पैदा हुई थी और 100 दिनों से अधिक समय तक एनआईसीयू में रही। उस कठिन समय के दौरान मेंटल सपोर्ट के लिए उन्होंने बच्ची के पास धीमी आवाज में महामृ-त्युंजय मंत्र जैसे मंत्र चलाए थे। प्रियंका ने बताया कि जन्म के वक्त बच्ची की हालत नाजुक थी। एक्ट्रेस ने कहा, "वह पर्पल (रंग) दिख रही थी।"

ईरान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ : जेडी वेंस

सनकी और क्रूर शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते

वॉशिंगटन, एजेंसी

मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वॉरशिप और सैनिकों की तैनाती के बीच उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी न समझा जाए और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल होगा। वेंस ने कहा कि सैन्य कार्रवाई की धमकियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फॉक्स न्यूज से बातचीत में वेंस ने कहा- हमें ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जहां ईरान, जो दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है, परमाणु आतंकवाद से दुनिया को धमकी न दे सके। सनकी, क्रूर और दुनिया के सबसे खतरनाक शासन को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन उनके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं और वे उनका इस्तेमाल करने की इच्छा दिखा चुके हैं। ट्रम्प ने बुधवार को संसद में अपने संबोधन के दौरान आरोप लगाया था कि

ईरान अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइलें विकसित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान पिछले साल अमेरिकी हमलों के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है कि किसी भी हमले की स्थिति में मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर होंगे। इससे क्षेत्र में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तय की गई शर्तों को ईरान मानने को तैयार नहीं है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में वेंस ने कहा कि बातचीत के कुछ हिस्से सकारात्मक रहे।

अमेरिका के 50 फाइटर जेट मिडिल ईस्ट पहुंचे

अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में पिछले हफ्ते 50 से ज्यादा फाइटर जेट भेजे। इंडिपेंडेंट फ्लाइट-ट्रैकिंग डेटा और मिलिट्री एविएशन मॉनिटर्स ने कई F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट को मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रिकॉर्ड किया गया। इन विमानों में से कुछ मिडिल ईस्ट में उतर चुके हैं। खासकर इजराइल के एयरबेस बेन गुरियन और ओवडा) पर, जहां अमेरिकी F-22 जेट को देखा गया और वहां लैंड करते हुए रिपोर्ट किया गया। यह जानकारी अमेरिका और ईरान के बीच 16 फरवरी को जिनेवा में हुई दूसरी दौर की बातचीत के दौरान सामने आई थी। दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते से जुड़े मुद्दों को लेकर मतभेद बने

वेंस बोले- बातचीत का अंतिम फैसला ट्रम्प के हाथ में है

जब वेंस से पूछा गया कि क्या ईरान के सर्वोच्च नेता को हटाना भी अमेरिका का लक्ष्य है, तो उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रम्प करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, ईरान अगले दो हफ्तों में ज्यादा बड़ा प्रस्ताव देगा, जिससे दोनों पक्षों के बीच मतभेद कम किए जा सकें।

ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर की बातचीत आज

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के अधिकारी गुरुवार यानी आज जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत करेंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची अपनी टीम के साथ जिनेवा पहुंच चुके हैं। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मिडिल ईस्ट दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे। वॉशिंगटन इस बीच 'मैक्सिमम प्रेशर' अभियान के तहत नए प्रतिबंधों की भी तैयारी कर रहा है। ईरान ने जिनेवा वार्ता से पहले अमेरिकी दबाव की रणनीति को खारिज किया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने ट्रम्प के बयानों को झूठ बताया और उन पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया। ट्रम्प ने कई बार चेतावनी दी है कि वार्ता विफल होने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

मनी-लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के सामने पेश हुए अनिल अंबानी

₹40 हजार करोड़ का बैंक कर्ज, ₹3,716 करोड़ का बंगला 'अबोड' कुर्क

मुंबई, एजेंसी

रिलायंस ग्रुप के पूर्व चेयरमैन अनिल अंबानी आज 26 फरवरी को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। अंबानी सुबह करीब 11 बजे जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और फंड के डायवर्जन को लेकर सवाल-जवाब किए जा रहे हैं। मामला सरकारी बैंकों से उनकी कंपनियों को मिले लोन में कथित गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सीबीआई की 2019 की FIR के आधार पर ED इस मामले की जांच कर रही है। एक दिन पहले ही जांच एजेंसी ने मुंबई के उनके 17 मंजिला घर 'अबोड' को कुर्क कर दिया था। अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के दूसरे

दौर के लिए पहुंचे हैं। आरोप है कि उनकी कंपनियों ने बैंकों से लिए लोन का डायवर्जन किया और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किया। इससे पहले अगस्त 2025 में उनसे पूछताछ हुई थी। ED के मुताबिक, रिलायंस कम्युनिके-शंस और उसकी ग्रुप कंपनियों ने देशी और विदेशी बैंकों से भारी कर्ज लिया था। वर्तमान में इन कंपनियों पर कुल बकाया ₹40,185 करोड़ है। बैंकों से लिए गए कर्ज की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के कारण इस बंगले को अस्थाई तौर पर कुर्क किया गया है। ये घर मुंबई के पॉश पाली हिल इलाके में स्थित है। अनिल अंबानी के इस 17 मंजिला घर की कीमत 3,716 करोड़ बताई गई है। प्रोविजनल अटैचमेंट का मतलब है कि प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से 'फ्रीज' कर दिया गया है ताकि आरोपी उसे बेचकर भाग न सके। जांच पूरी होने तक वे इस घर को किसी को ट्रांसफर भी नही कर सकते हैं। अगर कोर्ट में आरोप साबित हो जाते हैं, तब प्रॉपर्टी कब्जे में ले ली जा सकती है। हां, नवंबर 2025 में इसी केस में ED ने इसी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा कुर्क किया था, जिसकी कीमत 473.17 करोड़ थी। अब पूरी इमारत को इस कार्रवाई के दायरे में ले लिया गया है।

केजीएमयू में मजारें तोड़ने की कार्रवाई टली

4 अप्रैल तक की मोहलत मिली, रमजान-होली को देखते हुए समय दिया

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) परिसर में बनी मजारों को तोड़ने की कार्रवाई टल गई है। रमजान और होली को देखते हुए समय सीमा बढ़ाकर 4 अप्रेल कर दी गई है। हालांकि पहले नोटिस का संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोबारा नोटिस जारी किया है। साथ ही संबंधित कमेटियों को 28 फरवरी तक कुलसचिव के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। KGMU प्रशासन की ओर से 22 जनवरी को परिसर में स्थित मजारों को लेकर पहला नोटिस जारी किया गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय तक जवाब नहीं दिया गया तो इसे असहयोग माना जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। KGMU परिसर में स्थित अन्य पांच मजारों की कमेटियों ने पहले नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया।

पांच मजार कमेटियों की चुप्पी पर प्रशासन सख्त

KGMU परिसर में स्थित अन्य पांच मजारों की कमेटियों ने पहले नोटिस पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संस्थान की भूमि पर स्थित किसी भी ढांचे के संबंध में स्पष्ट और वैध दस्तावेज होना जरूरी है। इसी कारण गुरुवार को दोबारा नोटिस चस्पा कर सभी संबंधित कमेटियों को अंतिम अवसर दिया गया है।

न्यू ऑर्थोपेडिक परिसर की मजार ने दिया जवाब

न्यू ऑर्थोपेडिक परिसर में स्थित एक मजार की कमेटी ने प्रशासन को लिखित जवाब देते हुए दावा किया है कि संबंधित मजार वर्ष 1947 से पहले की है। कमेटी के अनुसार यह मजार ऐतिहासिक महत्व रखती है और इसका अस्तित्व आजादी से पहले का है। प्रशासन ने इस दावे को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। दस्तावेजों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जांच पूरी होने के बाद ही इस मजार के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

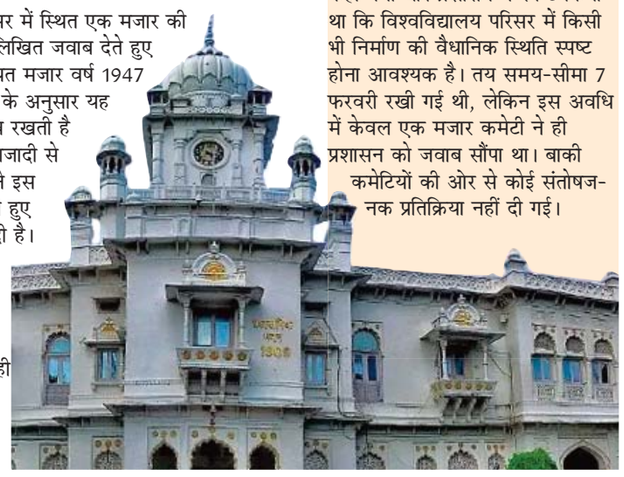

22 जनवरी को जारी हुआ था पहला नोटिस

इस नोटिस में मजारों की वैधता, निर्माण की तिथि और उनसे जुड़े आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी निर्माण की वैधानिक स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है। तय समय-सीमा 7 फरवरी रखी गई थी, लेकिन इस अवधि में केवल एक मजार कमेटी ने ही प्रशासन को जवाब सौंपा था। बाकी कमेटियों की ओर से कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

लखनऊ सिविल कोर्ट में पिस्टल-कारतूस समेत 2 युवक गिरफ्तार

1 पर एनआईए कोर्ट में चल रहा केस, चेकिंग के दौरान पकड़े गए

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ सिविल कोर्ट परिसर से 2 युवकों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आरोपी का केस एनआईए कोर्ट में चल रहा है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है। कोर्ट परिसर में हथियार ले जाने की मंशा अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार भानु प्रताप यादव राजाजीपुरम इलाके का रहने वाला है। उसका एक मामला एनआईए कोर्ट में विचाराधीन है। गुरुवार को वह कचहरी परिसर में प्रवेश करते समय गेट नंबर-8 पर रोका गया। तलाशी के दौरान उसके पास से फैक्ट्री मेड .32 बोर पिस्टल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के मुताबिक वह नशे में था और उसके पास एक ब्रीफकेस भी

मिला। प्रारंभिक पूछताछ में उसने पिस्टल को लाइसेंसी बताया, लेकिन मौके पर कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। दूसरा आरोपी लालचंद अमन विहार, ठाकुरगंज क्षेत्र का निवासी है। वह भानु प्रताप यादव के साथ कचहरी परिसर पहुंचा था। पुलिस ने दोनों को एक साथ हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस यह जांच कर रही है कि लालचंद की भूमिका क्या थी और वह किस उद्देश्य से भानु प्रताप के साथ न्यायालय परिसर आया था। कोर्ट परिसर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पिस्टल और कारतूस के साथ युवकों का पकड़ा जाना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि नियमित चेकिंग और सतर्कता के कारण ही दोनों को समय रहते पकड़ लिया गया। दोनों युवकों को संबंधित थाने ले जाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट परिसर में हथियार ले जाने के पीछे उनकी क्या मंशा थी। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हथियार लाइसेंसी है या अवैध।

फास्ट न्यूज

2 नाबालिग सहित 3 चोर गिरफ्तार

लखनऊ। लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में दो नाबालिग हैं। तीनों ऑटो से घूमकर रेकी करने के बाद घटना को अंजाम देते थे। आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद हुई है। इंस्पेक्टर मड़ियांव शिवानंद मिश्रा ने बताया कि पुलिस टीमें गश्त पर थी।

मां ने धनुष-बाण देकर अलंकार का स्वागत किया

कानपुर। कानपुर में अलंकार अग्निहोत्री का उनकी मां ने फरसा और धनुष-बाण देकर उनका स्वागत किया। समर्थकों ने देखो-देखो कौन आयाशेर आया और जिंदाबाद के नारे लगाए।अलंकार अग्निहोत्री ने मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मां, पत्नी और बहन सभी ने कहा- हमारा पूरा परिवार अलंकार के फैसले के साथ है। मां ने कहा- बेटा अन्याय के खिलाफ लड़ो, हम सब साथ हैं। अलंकार अग्निहोत्री ने अपना मोबाइल दिखाते हुए बताया कि पार्टी बनाने के बाद देश भर से लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। इसमें भाजपा और आरएसएस के लोग बड़ी संख्या में हैं। नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीतिक पार्टी बनाने वाले PCS अलंकार अग्निहोत्री गुरुवार दोपहर केशव नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। अलंकार अग्निहोत्री ने 23 फरवरी को वृंदावन में अपनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (राम) के गठन की घोषणा की थी।

ब्रज की संस्कृति को बढ़ावा देगी गीत-गोविंद वाटिका

आगरा। आगरा के ताजनगरी फेस-2 के जोनल पार्क में 27 फरवरी से गीत-गोविंद वाटिका का शुभारंभ होने जा रहा है। यहां ब्रज संस्कृति की झलक दिखाई देगी। भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का मंचन और धार्मिक आयोजन होंगे। प्रतिदिन शाम को यहां श्रीकृष्ण की लीलाओं पर आधारित साउंड एंड लाइट शो फाउंटेन पर हुआ करेगा। इस वाटिका का शुभारंभ 27 फरवरी को प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री तथा आगरा के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह करेंगे।

परिवर्तन चौक पर पुलिस की छात्रों से नोकझोंक

बोले- लखनऊ विश्वविद्यालय आरएसएस का अड्डा बना

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित लाल बारादरी सील किए जाने के विरोध में बापसा, भाकपा माले और आइसा के छात्रों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन पर रोक होने के कारण परिवर्तन चौक से स्वास्थ्य भवन चौराहे तक पैदल मार्च निकाला। मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल हुए। डीएम ऑफिस जाने पर अड़े प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान गुप्ता ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर ही पहुंचकर उनका ज्ञापन लिया। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का अड्डा बना दिया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के बाद लाल बारादरी सील किया गया है। इसके पहले 25 फरवरी की रात तौकील गाजी ने इस संबंध में एक वीडियासे जारी

प्रदर्शनकारियों को पैदल मार्च निकालने से पुलिस ने रोका। इस पर उनकी तीखी नोकझोंक हुई।

किया था। उसमें कहा था कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाल बारादरी पर ताला लगा दिया है। इसके खिलाफ हम लोगों ने विश्वविद्यालय में लगातार 2 दिन तक धरना दिया। विश्वविद्यालय प्रॉक्टर ने बातचीत करके 2 दिनों का समय मांगा था, लेकिन वह बीत गया।

बसपा विधायक के घर से 11 करोड़ कैश मिला

महंगी घड़ियां-जेवर बरामद, 1000 करोड़ टैक्स चोरी में दूसरे दिन भी रेड

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के ठिकानों पर आयकर विभाग (IT) की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। सोनभद्र, कौशांबी और बलिया में कार्रवाई चल रही है, जबकि लखनऊ के आवास पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, यहां से टीम को करीब साढ़े 11 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। इसके अलावा महंगी घड़ियां, सोना-चांदी और कीमती जेवर भी बरामद हुए हैं। बुधवार को आयकर टीम ने एक साथ 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक, आयकर विभाग 1000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के मामले में फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य रिकॉर्ड खंगाल रहा है। हालांकि, आधिकारिक तौर पर बरामदगी की पुष्टि नहीं की गई है। लखनऊ में बुधवार सुबह साढ़े सात बजे शुरू हुई कार्रवाई आज सुबह 9 बजे तक चली। करीब 50 अधिकारियों ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान किसी के भी अंदर-बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी।

मायावती बोलीं- विधायक गंभीर बीमार, बाद में भी छापा मार सकते थे

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा- जब से उमाशंकर सिंह बीएसपी में आए हैं, उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उनके क्षेत्र से अब तक अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने या किसी अन्य गलत काम की कोई शिकायत नहीं मिली है। वह 2 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर आयकर विभाग को उनके संबंध में कोई शिकायत मिली भी थी, तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ठीक होने के बाद पूछताछ की जा सकती थी।

2017 में अयोग्य घोषित हुए थे

14 जनवरी, 2017 को तत्कालीन राज्यपाल राम नाइक ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। उन पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के उल्लंघन का आरोप था। मामला सरकारी ठेके अपने नाम पर लेने से जुड़ा था। लोकायुक्त की जांच में आरोप सही पाए गए थे। बाद में हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। यह प्रदेश का पहला मामला था, जब किसी विधायक की सदस्यता पिछली तारीख से समाप्त की गई।

मंत्री दिनेश सिंह ने कहा- बिटिया का फोन आया था। रो-रोकर बताया कि बेरहमी के साथ बर्ताव किया जा रहा है। उमाशंकर जी को चौथे स्टेज का कैंसर है। सब अच्छी तरह से जानते हैं कि 2 साल से जिंदगी-मौत से संघर्ष कर रहे हैं। उनके सारे धंधे बंद हो चुके हैं। परिवार इलाज कराने में कभी अमेरिका, दिल्ली लखनऊ के बीच में दौड़ रहा है। अगर उनके जीवन को कोई नुकसान होता है, तो इसकी जिम्मेदारी ये संवेदनहीन संस्थाएं होंगी। ऐसे हालात में तो अदालतें गंभीर अपराधों में भी मानवीय आधार पर राहत देती हैं।

अखिलेश बोले- कुछ लोग जापान गए, इसलिए छापा पड़ा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा- उमाशंकर जी के यहां छापा इसलिए पड़ा, क्योंकि कुछ लोग जापान गए हैं। अगर जापान न जाते, तो छापा ना पड़ता। पुलिस को पता चल जाता है। पुलिस लीक कर देती है। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर बसपा के विधायक हैं। भाजपा का अगर कोई है, तो उस पर छापा नहीं पड़ता। भाजपा को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा।

बोलेरो 40 फीट नीचे नहर में गिरी, चारों दरवाजे उखड़े

बिजनौर में शादी से लौट रहे थे 6 दोस्त, उत्तराखंड के दो युवकों की मौत

तमसा संकेत, एजेंसी

बिजनौर। बिजनौर में 40 फीट ऊंचाई से बोलेरो नहर में गिर गई। हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई। जबकि, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक उत्तराखंड के रहने वाले थे। सभी 6 दोस्त शादी में शामिल होने के लिए उत्तराखंड से आए हुए थे। शादी अटेंड करने के बाद युवक उत्तराखंड लौट रहे थे, इसी दौरान कार बेकाबू हो गई। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बोनट का हिस्सा पूरा उखड़ के अलग हो गया। कार के सभी दरवाजे भी अलग हो गए। 7 फीट की बोलेरो, महज 4 फीट की रह गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार के अंदर फंसे युवकों को बाहर निकाला। सभी को तुरंत

इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया। 4 घायलों का एम्स ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। घटना जिला मुख्यालय से 45 किमी दूर नजीबाबाद-हरिद्वार बाईपास की है। नजीबाबाद में बुधवार देर रात शादी समारोह से लौट रहे 6 दोस्त बोलेरो कार से वापस लौट रहे थे7 तभी कोहरे के बीच कार अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगनहर में जा गिरी। हादसा रात करीब 2 बजे समीपुर नहर के पास नजीबाबाद–हरिद्वार बाईपास रोड पर हुआ। कार करीब 40 फीट गहरी नहर में समा गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। मरने वालों की पहचान सतीश (55) पुत्र किरनदास, निवासी मुनिकीरेती ऋषिकेश और सचिन (36) पुत्र अनूप कुमार, निवासी गांव मानियावाला थाना अफजलगढ़ के रूप में हुई है। सतीश होटल लाइन में काम करते थे, जबकि सचिन जेसीबी चालक थे। सचिन की शादी 2017 में हुई थी और उनका एक बच्चा है। घायलों में विशाल कुमार, मोहित, नितिन विशाल और विशाल कश्मीरी शामिल हैं। सभी दोस्त बताए जा रहे हैं।

मौत: अकेला पाकर घर में घुसा पड़ोसी, भाई के आते ही छत से कूद कर भागा

9वीं की छात्रा से छेड़छाड़, सुसाइड किया

पुलिस ने छात्रा के शव का पोस्टमॉर्टम करवाया है। फरार आरोपी को हिरासत में ले लिया है।

तमसा संकेत, एजेंसी

झांसी। झांसी में छेड़छाड़ से आहत 9वीं कक्षा की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। वह बुधवार को घर पर अकेली थी। तभी दोगुनी उम्र का पड़ोसी घर में घुस आया। कमरे की कुंडी बंद करके छात्रा से जबरदस्ती करने लगा। तभी स्कूल से छात्रा का छोटा भाई घर पहुंच गया। उसने दरवाजा खोला तो आरोपी गंदी हरकत कर रहा था और छात्रा रो रही थी। भाई को देखते ही आरोपी छत से कूदकर भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छात्रा ने बेइज्जती होने के डर से गुरुवार सुबह जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी ले

गए। वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना मौंठ थाना क्षेत्र की है। मृतका की मौसी ने बताया- मैं और मेरी बड़ी बहन की शादी एक ही घर में हुई है। बड़ी बहन की 16 साल की एक बेटी और 8 साल के जुड़वा बेटी-बेटा है। जीजा ट्रक चलाते हैं। 23 फरवरी को बड़ी बहन भतीजे की शादी में अपने मायके गई थी। वह छोटी बेटी को भी साथ ले गई थी। घर पर बड़ी बेटी और उसका छोटा भाई ही थे।

मौसी ने आगे बताया- बच्चों ने घर की बाहर से कुंडी बंद कर दी। तब आरोपी वीरू छत से कूदकर भाग गया। उसने मुझे फोन किया और रोते हुए घटना बताई। तब मैं घर पहुंची। आरोपी रास्ते में मिला और हाथ-पैर जोड़कर गलती मानने लगा। मैंने घर पहुंचकर डायल 112 पर फोन किया और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी को घर से पकड़ लिया और अपने साथ ले गई। मैंने घटना की जानकारी उसकी मां को दी। उनको गुरुवार को घर लौटना था। उसके पिता भी घर आ रहे थे।

मैं भी उसी घर में अपने बच्चों के साथ रहती हूं। बड़ी बेटी के पेपर हो चुके थे, इसलिए वह स्कूल नहीं जा रही थी। बुधवार दोपहर को मैं खेत पर चली गई। बच्चे स्कूल गए थे। बड़ी बेटी घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस का वीरेंद्र उर्फ वीरू साहू घर में घुस आया। घर की अंदर से कुंडी बंद करके बेटी से छेड़छाड़ करने लगा। इस दौरान छुट्टी होने पर बड़ी बेटी का भाई और मेरा बेटा घर पहुंचे। दोनों ने हाथ डालकर कुंडी खोली। अंदर देखा तो आरोपी वीरू बेटी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वह रो रही थी मौसी ने आगे बताया- घटना के बाद से बेटी डिप्रेशन में थी। गुरुवार सुबह उठने के बाद से उसने घर का काम किया। पूरे गांव में घटना की चर्चा हो रही थी।

पृष्ठ 01 का शेष...

यूपी और...

इसके तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जहां प्रकृति की विशेष कृपा है। भारत की सबसे उर्वर भूमि, सर्वाधिक जल संसाधन, विशाल मानव संसाधन और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक विरासत उत्तर प्रदेश को विशेष पहचान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है और पिछले नौ वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय व अर्थव्यवस्था तीन गुना करने में सफलता मिली है। आज उत्तर प्रदेश भारत की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। कभी 'बीमारू' कहा जाता था, आज ग्रोथ इंजन बना योगी ने टोक्यो में निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा था कि यूपी में 25 करोड़ की आबादी के साथ देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। राज्य की जितनी बड़ी आबादी है, उतनी ही विशाल संभावनाएं हैं। पिछले नौ साल में राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हो गई है। जो प्रदेश कभी 'बीमारू' कहा जाता था, वह आज भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। दीपों से जगमगाता आज का अयोध्या योगी ने अयोध्या दीपोत्सव का जिक्र करते हुए कहा था कि साल 2017 से पहले दीपावली इस भव्यता के साथ नहीं मनाया जाता था। सरकार बनने के बाद हमने दीपोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया। पहली बार जब दीप प्रज्ज्वलन की योजना बनी, तब 51 हजार दीपक भी अयोध्या और आसपास उपलब्ध नहीं थे। उस समय पूरे प्रदेश से 51 हजार दीपक इकट्ठे किए गए थे।

दिल्ली हाईकोर्ट...

जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (AFT) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी की दिव्यांग पेंशन याचिका खारिज कर दी गई थी। वे हाई ब्लड प्रेशर (हाइपर-टेंशन) और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना किसी ठोस वजह के बीमारी को सिर्फ 'लाइफस्टाइल डिसऑर्डर' कहना कानूनन सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी बताया कि मेडिकल बोर्ड ने खुद माना था कि यह बीमारी अधिकारी की किसी लापरवाही या गलत आदतों की वजह से नहीं हुई। कोर्ट ने मोटापा, धूम्रपान या शराब से जुड़े तर्क भी खारिज कर दिए, क्योंकि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में इन्हें कारण नहीं बताया गया था। सिर्फ वजन ज्यादा होना, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोग को खुद से पैदा हुई बीमारी साबित नहीं करता। कोर्ट ने यह भी कहा कि AFT ने बिना मेडिकल सबूत के वजन और लाइफस्टाइल के आधार पर निष्कर्ष निकाले। कोर्ट ने हृदय रोग को लेकर मेडिकल बोर्ड की दलीलों को भी कमजोर बताया और कहा कि बीमारी को सिर्फ पिछले 14 दिनों की ड्यूटी से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। याचिकाकर्ता रिटायर्ड अफसर ने भारतीय वायुसेना में 40 साल से अधिक सेवा दी थी। ज्वाइनिंग के समय वह मेडिकल रूप से फिट थे। 1999 में उन्हें हाईपरटेंशन हुआ और 2016 में गंभीर कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ओपन-हार्ट सर्जरी करानी पड़ी। उनकी दिव्यांगता 50% आंकी गई थी, फिर भी पेंशन से वंचित कर दिया गया। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए 50% आजीवन दिव्यांग पेंशन देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने रिटायरमेंट की तारीख से बकाया भुगतान 8 सप्ताह के भीतर जारी करने को कहा है।

भारतीय यूपीआई...

इस नरसंहार को होलोकॉस्ट कहा जाता है। इजराइल की संसद नेसेट ने साल 1953 में फैसला किया कि होलोकॉस्ट में मारे गए लोगों की याद में एक खास स्मारक बनाया जाए। बाद में 2005 में यहां एक आधुनिक संग्रहालय खोला गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इस त्रासदी को समझ सकें। याद वाशेम परिसर में होलोकॉस्ट संग्रहालय, हॉल ऑफ नेम्स, बच्चों का स्मारक और राइटियस अमंग द नेशंस गार्डन जैसी जगहें मौजूद हैं। यहां असली दस्तावेज, तस्वीरें और पीडितों की व्यक्तिगत कहानियां सुरक्षित रखी गई हैं। याद वाशेम नाम का अर्थ है याद और नाम, यानी जिन लोगों को मिटाने की कोशिश की गई, उनकी याद हमेशा जिंदा रहे।

भाजपा को हराना...

जिससे खास वर्ग के मतदाताओं के वोट काटे जा सकें। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे हर पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने में मदद करें और मतदाता सूची की लगातार निगरानी रखें, ताकि किसी भी पात्र मतदाता को उसके अधिकार से वंचित न किया जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और युवाओं के साथ छल कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के साथ होने वाले समझौते से भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है और इससे देश की कृषि व्यवस्था प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की आर्थिक नीतियां जनविरोधी हैं और इन नीतियों के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। उनके अनुसार, मौजूदा हालात में गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर और अधिक समृद्ध हो रहे हैं।

शंकराचार्य के खिलाफ साजिश हो रही : संजय सिंह

गिरफ्तारी हुई तो आप पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी

तमसा संकेत, एजेंसी

लखनऊ। लखनऊ में आप नेता संजय सिंह ने कहा- शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ साजिश की जा रही है। उनके खिलाफ जिस व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है। उसका खुद का आपराधिक इतिहास है। अगर शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया तो आप पार्टी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। उत्तर प्रदेश के 9 लाख 12 हजार करोड़ रुपए के बजट पर कहा- बजट का आकार बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सरकार 'आंकड़ों की कारीगरी' कर जनता को गुमराह कर रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि 2025-26 की तुलना में कई विभागों में वास्तविक खर्च कम हुआ है, जबकि सरकार बढ़ोतरी का दावा कर रही है। प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें

माघ मेला-2026 और महाकुंभ-2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूंसी थाने में FIR दर्ज की गई। FIR में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। 24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया।

तमसा संकेत
tamsa.newslko@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक विद्या देवी द्वारा कृष्णा डाइनेस्टी प्रिंटिंग प्रेस म0 न0 195 सेक्टर 6-बी, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड लखनऊ-226 029 (उ0प्र0) से मुद्रित व प्रकाशित।

सम्पादक : विद्यादेवी

समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा

समाचार पत्र में प्रकाशित लेख, राजनीतिक विश्लेषण, लेखकों के अपने विचार हैं। सम्पादक का इन विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं हैं।
मो0- 9415799533
R.N.I. NO. UPHIN/2021/83676